>

Title: Need to accord approval for electrification of hamlets (majras) under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana in Uttar Pradesh and ensure supply of electricity to villages covered under the scheme particularly in Deoria parliamentary constituency.

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केन्द्र सरकार ने लागू की । इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मजरों के विद्युतीकरण के लिए धनराशि की मांग की थी उस समय केन्द्र सरकार ने कहा कि सभी प्रदेशों में सभी गांवों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जाये तो मजरों के विद्युतीकरण किये जाने की स्वीकृति दी जाएगी । केन्द्र सरकार ने कई प्रदेशों में मजरो की विद्युतीकरण कार्य को मंजूरी दे दी है परंतु उत्तर प्रदेश को अभी तक यह मंजूरी नहीं दी गई है । जबकि उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं । वर्ष 2009 में 1,37,060 मजरों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ने दिया परंतु केन्द्र सरकार ने अपने नेताओं के संसदीय क्षेत्र रायबरेली एवं सुल्तानपुर के अलावा किसी और जनपद की स्वीकृति नहीं दी है इन सबके कारण अनुसूचित जाति के कई हजार गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है ट्रंसफार्मर बन गये हैं, परंतु उन पर से कनैक्शन नहीं दिये गये हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र के लार इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची हैं जहां पर दलित बस्तियाँ है जिनकी वजह से यहां के लोग बुनियादी सुविधाओं सं वंचित है और बच्चों का पठन पाठन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है । कई जगहों पर खम्बे लग गये हैं परंतु उन पर तार नहीं बिछाये गये हैं ।

सरकार से अनुरोध है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समुचित ढंग से एवं समय पर इसके क्रियान्वयन के लिए प्रयास किये जाए ।